जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

Metro

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

ARBiT

When "Back of Beyond" Becomes the Centre Stage

Dr. Pankaj Jha then complicated the easy, monochrome story of Rajasthan that popular culture loves. It was not to deny confrontation, but to foreground something less theatrical, and therefore often neglected

Merci, France, for the Mansard Roof!

भाजपा के मंत्री व सांसद भी प्रियंका की तारीफ करते देखे गए संसद में

शीतकालीन सत्र के अंतिम दिनों में राहुल की गैर मौजूदगी में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 दिसंबर। संसद के शीतकालीन सत्र के आख़िरी दिनों में राहुल गांधी जर्मनी में थे, इसलिए बड़े भाई की गैरमौजूदगी में संसद में पार्टी की कमान और पूरे घटनाक्रम को सँभालने की ज़िम्मेदारी प्रियंका गांधी पर आ गई।

उन्होंने बेहद शानदार प्रदर्शन किया। प्रियंका गांधी एक स्वाभाविक नेता के रूप में सामने आईं, एक स्टार लीडर, जो फ्रंट लाइन पर आकर नेतृत्व करता है। सोशल मीडिया और मीडिया में उनकी खूब चर्चा हुई, उनकी तस्वीरें और वीडियो हर जगह छाए रहे और मीडिया उन्हें बार-बार दिखाता रहा।

इंदिरा गांधी की तरह नज़र आने वाली प्रियंका गांधी एक आकर्षक, मुस्कुराती हुई, धैर्यवान नेता के रुप में उभरीं। वे पूरे जोश के साथ बोलीं, लेकिन संयम बनाए रखा। उन्होंने सत्र के अंत में स्पीकर द्वारा की गई परंपरागत चाय पार्टी में प्रधानमंत्री मोदी से शिष्टाचार बातचीत भी की।

- प्रियंका की जोशीली किन्तु संयमित भाषण शैली के साथ-साथ उनके शिष्ट व्यवहार ने भी लोगों का दिल जीत लिया।
- उनकी आकर्षक मुस्कुराती छवि में लोगों को इंदिरा गांधी की झलक नज़र आई।
- सत्र के अंतिम दिन स्पीकर की औपचारिक चाय पार्टी में प्रियंका ने प्र.मंत्री मोदी से उनकी विदेश यात्रा के बारे में पूछा व कुछ अनौपचारिक बातें भी कीं, नितिन गडकरी के साथ भी उन्होंने बात की।
- प्रियंका का यह शालीन तथा शिष्ट व्यवहार सोशल मीडिया पर छाया रहा।
- प्रियंका को जो लोकप्रियता और वाहवाही मिली, उसे देखकर राहुल की टीम को राहुल के जर्मनी प्रवास पर अवश्य ही खेद हो रहा होगा।

वंदे मातरम् पर प्रियंका गांधी का भाषण काफी वायरल हुआ और बड़ी संख्या में लोगों ने उनके भाषण का वीडियो देखा और सराहा।

संसद में मनरेगा का नाम बदलने के विरोध में उन्होंने सभी विपक्षी दलों को साथ लेकर विरोध का नेतृत्व किया।

इसके बिल्कुल उलट, राहुल गांधी को एक "एंग्री यंग मैन" के रूप में देखा जाता है, जिनके भाषणों में आक्रामकता, नाराज़गी और भाजपा नेतृत्व पर तीखा हमला ज़्यादा दिखता है।

भाई और बहन की शैली अलग-अलग है। दोनों भाजपा सरकार के ख़िलाफ़ एक जैसा संदेश देते हैं, लेकिन बिल्कुल अलग तरीकों से।

राहुल की अनुपस्थिति में संसद के शीतकालीन सत्र के आख़िरी तीन दिनों में जो देखा गया, वह था प्रियंका गांधी का उदय। उन्हें राहुल गांधी की तुलना में कहीं ज़्यादा फोकस, प्रतिक्रिया और तालियाँ मिलती देखी गईं।

चाय पार्टी के दौरान प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से पूछा, उनकी विदेश यात्रा कैसी रही। उन्होंने मोदी को बताया कि गले में ख़राश के लिए वे वायनाड से केरल की एक खास जड़ी-बूटी मंगवाती हैं, जो दिल्ली के प्रदूषण से राहत दिलाती है।

यह सब शालीन और सभ्य

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजस्थान में नये साल से ईवनिंग कोर्ट की तैयारी

जयपुर, 20 दिसंबर। नए साल से राजस्थान में इवनिंग कोर्ट आरंभ करने की कवायद की जा रही है। इसके तहत, नियमित समय के बाद शाम के समय भी अदालतों में सुनवाई होगी। हाईकोर्ट प्रशासन ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया है।

जानकारी के अनुसार, फिलहाल जोधपुर और जयपुर में एक-एक मजिस्ट्रेट कोर्ट को यह जिम्मेदारी दी गई है। इन अदालतों में फिलहाल चेक बाउंस जैसे प्रकरणों को लाया जाएगा।

- जयपुर व जोधपुर में प्रयोग सफल हुआ तो पूरे प्रदेश में लागू होगा।

यदि इवनिंग कोर्ट का यह प्रयोग सफल रहा तो इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जा सकता है।

दूसरी ओर, राजस्थान हाईकोर्ट की हाल ही में हुई फुल कोर्ट की मीटिंग में तय किया गया है कि नए साल से अब हर माह दो शनिवार को मुकदमों की सुनवाई की जाएगी। इसके लिए साल 2026 के कैलेंडर में संशोधन भी कर दिया गया है। ऐसे में अब अगले साल से हाईकोर्ट में 24 दिन मुकदमों की अतिरिक्त सुनवाई होगी। फिलहाल हाईकोर्ट में हर शनिवार का अवकाश रहता है। बताया जा रहा है कि माह में दो दिन अतिरिक्त सुनवाई होने से लंबित मुकदमों की संख्या में काफी हद तक कमी आएगी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

वो दिन गए, जब भाजपा सहयोगी दलों की "मेहरबानी" पर निर्भर नज़र आती थी

हालांकि, अभी भी भाजपा की केन्द्रीय सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, पर, बिहार की जीत ने सहयोगी दलों व भाजपा के संबंधों के समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 दिसंबर। बिहार में जीत के बाद भाजपा के दो सबसे बड़े चेहरे-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह-ने एनडीए के भीतर और बाहर, दोनों जगह अपनी पकड़ एक बार फिर मज़बूती से स्थापित कर ली है।

हालिया घटनाक्रम इस बदलाव की ओर इशारा करते हैं: सरकार द्वारा यूपीए दौर के दो प्रमुख क़ानूनों को हटाने के लिए वीबी-जी राम जी और एसएचएएनटीआई (शांति) विधेयक लाने पर एनडीए पार्टनर्स का समर्थन, बीमा क़ानून में संशोधन, एसआईआर के मुद्दे पर सरकार का झुकने से इनकार, और "वंदे मातरम्" को लेकर भाजपा का आक्रामक अभियान।

भाजपा के पास अब भी लोकसभा में पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन वे दिन अब दूर जा चुके हैं, जब पार्टी को चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की जेडीयू जैसी सहयोगी पार्टियों की कृपा पर निर्भर रहना पड़ता था। उदाहरण के लिए, टीडीपी आंध्र प्रदेश में एसआईआर कराए जाने के फ़ैसले से कथित तौर पर नाराज़ है, लेकिन चुनाव आयोग ने वहाँ इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय ले लिया है।

- चंद्रबाबू नायडू नहीं चाहते थे, एसआईआर की कार्यवाही आँध्र में करवाई जाए, पर, चुनाव आयोग ने बोगस मतदाता व जायज मतदाता को पहचानने की कार्यवाही आँध्र में बेखटके जारी रखी।
- नीतीश कुमार भी हालांकि, बिहार में मु.मंत्री बने हैं, पर, उनकी उतनी नहीं चल रही, जितनी पहले चलती थी।
- इसी प्रकार छोटी-छोटी सहयोगी पार्टियों की राजनीतिक सोच में न्यूक्लियर एनर्जी विधेयक (शांति बिल) फिट नहीं बैठता, पर, सभी सहयोगी दलों ने केन्द्रीय सरकार के इन तीनों विधेयकों के पक्ष में ही मतदान किया, संसद में।
- काफी चर्चा थी कि संघ नये भाजपा अध्यक्ष के पद पर अपने आदमी को लाना चाहता है, नितिन नबीन के अध्यक्ष बनने से पीढ़ी परिवर्तन तो जरुर हुआ, पर, इसे संघ की जीत नहीं माना जा सकता।

इसी तरह, 'सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फ़ॉर ट्रांसफ़ॉर्मिंग इंडिया' (एसएचएएनटीआई-शांति) विधेयक, जो निजी क्षेत्र को परमाणु बिजली संयंत्रों के संचालन में शामिल करने के लिए भारत के परमाणु ऊर्जा कानूनी ढांचे में बड़ा बदलाव करता है, छोटे एनडीए पार्टनर्स की राजनीति से मेल नहीं खाता। इसके बावजूद, इन दलों ने संसद के अभी समाप्त हुए शीतकालीन सत्र में भाजपा द्वारा पेश किए गए इस विधेयक

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भाजपा का पलटवार है कि मनरेगा में परिवर्तन का विरोध क्यों है?

बिहार में 4.33 लाख जॉब कार्ड फर्जी लाभार्थियों के बनते थे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 दिसंबर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में एक भावनात्मक मुद्दे पर सहमति जताते हुए इसके नाम में महात्मा गांधी का नाम जोड़ने का निर्णय लिया है, साथ ही उन्होंने संसद में गुरुवार को पारित विकासशील भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी जी राम जी) बिल के सभी प्रावधानों को लागू करने पर जोर दिया।

विपक्षी दल इस बिल का विरोध करने के लिए एकजुट हो गए थे, लेकिन संसद में जो नाटक हुआ, वह ग्रामीण श्रमिकों की मदद के लिए नहीं, बल्कि बिचौलियों को अपना हिस्सा खोने से बचाने के लिए था। वे इस योजना का 40 प्रतिशत भार राज्य सरकारों पर डालने के खिलाफ थे, और दावा कर रहे थे कि इससे राज्य सरकारों का बजट बिगड़ जाएगा।

- नई स्कीम में 40 प्रतिशत खर्चा राज्य सरकार का होने लगेगा तो सरकारी तंत्र, "ब्यूरोक्रेसी", अपने आप सतर्क हो जाएगी कि सही खर्चा ही होगा, फर्ज़ी लाभार्थी दिखाकर, पैसा उठाने पर अपने आप अंकुश लगेगा।
- विपक्ष इस बात से परेशान है कि उनका उस "संरक्षण उद्योग" (पैट्रोनेज़ इण्डस्ट्री) पर नियंत्रण खत्म हो जाएगा, जो अब तक फर्ज़ी लाभार्थियों के कारण बेधड़क चल रहा था।

मोदी सरकार ने जोर दिया कि केन्द्र सरकार 60 प्रतिशत खर्च वहन करेगी, शेष 40 प्रतिशत राज्य सरकार देगी। इसके पीछे कारण था, जैसा कि उन्होंने बिहार में 4.33 लाख मनरेगा जॉब काड्र्स के बारे में बताया, जो कागजों

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

रविवार को लखपति दीदियों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री

जयपुर, 20 दिसम्बर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार (21 दिसम्बर) को ओटीएस सभागार में राज्य स्तरीय लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम में राजीविका के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी लखपति दीदियों के साथ संवाद करेंगे।

इस दौरान, मुख्यमंत्री लखपति दीदियों के साथ उनकी आत्मनिर्भरता की यात्रा पर चर्चा करेंगे। साथ ही, विभिन्न जिलों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ी लखपति दीदियों से बातचीत कर उनके अनुभव भी जानेंगे। मुख्यमंत्री लखपति दीदियों को टेबलेट भी वितरित करेंगे।

- वे विभिन्न जिलों की लखपति दीदियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संवाद करेंगे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सोनिया गांधी यू.पी.ए. सरकार में मनरेगा स्कीम की प्रेरणास्त्रोत व जननी मानी जाती थीं

अतः अब उन्हें इस स्कीम के सोच व क्रियान्वयन में परिवर्तन व्यक्तिगत तौर असहनीय हो रहा है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर। ग्रामीण रोज़गार गारंटी क़ानून में प्रस्तावित बदलावों को लेकर मोदी सरकार पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी का तीखा हमला देश भर के पार्टी नेताओं के लिए एक साफ़ राजनीतिक संकेत बनकर उभरा है कि अब लंबे और लगातार टकराव के लिए तैयार रहा जाए।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा संसद के भीतर और बाहर दिए गए कड़े वीडियो संदेश ने सत्तारूढ़ एनडीए को हिला दिया है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार रक्षात्मक मुद्रा में आ गई है।

- कांग्रेसाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह व्यक्तिगत पीड़ा भांपते हुए, 27 दिसंबर की सी.डब्ल्यु.सी. की बैठक मनरेगा में परिवर्तन के मुद्दे को लेकर रखी है।
- कांग्रेस हाईकमान मानती है, इस मुद्दे की प्रतिध्वनि देश के पूरे ग्रामीण इलाकों में होगी तथा कांग्रेस इस विरोध को देश व्यापी आंदोलन का रूप देगी।
- कांग्रेस का इस आंदोलन में नारा होगा, सरकार केवल स्कीम का नाम नहीं बदल रही, उसकी आत्मा खत्म कर रही है, जिससे मनरेगा वर्कर का आत्मसम्मान जुड़ा है।
- सी.डब्ल्यु.सी. की बैठक "रोड मैप" तैयार करेगी, रैली, प्रदर्शन का, प्रदेश के संगठनों से समन्वय स्थापित करके तथा इस आंदोलन को मोदी सरकार के खिलाफ आक्रमण को मुख्य आधार बनाएगी।

लड़ाई को एक क़दम आगे बढ़ाते हुए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 27 दिसंबर को कांग्रेस

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)